आठ करोड़ प्रदेशवासी ही मेरा परिवार- भजनलाल शर्मा

ऐतिहासिक बजट के लिए केकड़ी के निवासियों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार

गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर केकड़ी जिले के निवासियों ने बजट में क्षेत्र के लिए मिली ऐतिहासिक सौगातों के लिए मुख्यमंत्री का एक समारोह में आभार जताया।

- मुख्यमंत्री ने कहा कि केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने क्षेत्र के विकास कार्यों के संकल्प के क्रम में चरण पादुका त्याग रखी है। वे जल्दी ही चरण पादुका पहनेंगे क्योंकि इस बजट में केकड़ी जिले को कई ऐतिहासिक सौगातें मिली हैं।

जयपुर, 18 जुलाई (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार जनप्रतिनिधियों की क्षेत्र से संबंधित विकास की मांगों पर तत्परता से कार्य कर रही है। पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, विधायक सहित समस्त जनप्रतिनिधि क्षेत्र की नब्ज जानते हैं, इसलिए हमने बजट में उनके फीडबैक और सुझावों के आधार पर प्रदेश की आठ करोड़ जनता के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा, आठ करोड़ प्रदेशवासी ही मेरा परिवार हैं और हमने बजट में सभी क्षेत्रों की मांग को पूरा किया है।

शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर केकड़ी जिले के निवासियों के आभार समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का वर्ष 2024-25 का परिवर्तित बजट प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस ऐतिहासिक बजट में गांव, ढाणी, शहर एवं छोटे-बड़े जिलों में विकास का ऐसा रोडमैप तैयार किया गया है, जिससे "आपणो अग्रणी राजस्थान" का संकल्प साकार होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए सबसे पहले सोचकर योजनाओं-कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। जनता भी अपने आस-पास वंचितों की पहचान कर उन्हें लोककल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में दूरगामी कदम उठाते हुए "एक पेड़ मां के नाम" अभियान की शुरूआत की है। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से आव्हान किया कि वे अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगाकर इस अभियान को सफल बनाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने क्षेत्र के विकास कार्यों के संकल्प के क्रम में चरण पादुका त्याग रखी हैं। वे जल्दी ही चरण पादुका पहनेंगे क्योंकि इस बजट में केकड़ी जिले को कई ऐतिहासिक सौगातें मिली हैं, जिससे क्षेत्र का चहुंमुखी विकास सुनिश्चित होगा।

इस अवसर पर गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसान, युवा, महिला एवं वंचितों के कल्याण के लिए बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। बजट में केकड़ी जिले की हर मांग पूरी हुई है, जिसके लिए उनका कोटि-कोटि धन्यवाद।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 650 करोड़ रुपए की लागत से नसीराबाद-सरवाड़-केकड़ी-देवली सड़क को 4 लेन का बनाया जाएगा। इसके अलावा, 81 लाख रुपये की लागत से थड़ोली से केकड़ी के मध्य भांसू गांव के समीप पेयजल पाइप लाइन का कार्य एवं 20 करोड़ रुपये की लागत से बिजयनगर-नगर-बडली-माताजी का खेड़ा व देवलियाकलां सडक (बिजयनगर, भिनाय)- केकडी का कार्य करवाया जायेगा। कार्यक्रम में केकडी जिले के जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह एवं पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका अभिनन्दन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केकडी के निवासियों के साथ संवाद भी किया।

नाबालिग का ....

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि अभियुक्त उसके पड़ोस में रहने वाली भाभी का भाई है। इसके चलते उसकी अभियुक्त से पहचान हो गई थी। घटना की रात अभियुक्त उसे डरा धमकाकर अपने साथ मोटरसाइकिल से अराई ले गया, जहां एक कच्चे मकान में अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद एक किशोर और अभियुक्त उसे मोटर साइकिल से जोधपुर ले गए। यहां किशोर ने उसके साथ दो बार दुष्कर्म किया। इसके बाद किशोर उसे अपने घर ले गया। वहीं बाद में पुलिस उसे आकर ले गई। दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसका परिवादी पक्ष से जमीन का झगडा चल रहा है। ऐसे में उसे प्रकरण में फंसाया गया है। इसलिए उसे बरी किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई।

सुप्रीम कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मूल रूप से मणिपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति सिंह अपने राज्य के पहले न्यायाधीश हैं जिन्हें उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत किया गया। न्यायमूर्ति महादेवन मूलतः तमिलनाडु उच्च न्यायालय से आते हैं।

'पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत बिजली क्षेत्र में प्रदेश के हितों पर कुठाराघात नहीं करें'

- ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर ने गहलोत पर निम्न स्तर की राजनीति करने का आरोप लगाया।
- नागर ने कहा, छत्तीसगढ़ सरकार चरणबद्ध तरीके से सहयोग कर रही है और हमें रोज 9 रैक कोयला मिल रहा है।

जयपुर, 18 जुलाई (का.सं.)। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से राजस्थान को जो सहयोग किया गया है, उस पर विपक्ष द्वारा आदतन झूठ फैला कर प्रदेश की जनता को गुमराह किया जाना अति निंदनीय है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को प्रदेश के हितों पर कुठाराघात करते हुए ओछी राजनीति करने से बाज आना चाहिए।

उन्होंने गहलोत से सवाल किया कि उनकी सरकार के समय बिजली क्षेत्र में जनता के हितों का ध्यान क्यों नहीं रखा गया।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पीईकेबी की 91 हेक्टेयर भूमि की साइट क्लीयरेंस अनुमति 12 दिसम्बर 2023 को दी गई थी, इसमें से 26 हेक्टेयर भूमि 19 जनवरी 2024 को तथा 30 हेक्टेयर भूमि 22 मार्च को राजस्थान सरकार को सौंप दी गई, जिससे प्रति दिन 9 रेक कोयला मिल रहा है और इसके लिए हमने धन्यवाद व्यक्त किया था। शेष 34 हेक्टेयर के लिए भी क्लीयरेंस दे दी गई है, तथा यह जमीन भी जल्द ही प्राप्त हो जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि कुछ बिंदु अभी भी लंबित तथा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपने बयान में इन्हीं अनुरोधों के पूर्ण न होने की ओर इशारा कर रहे थे।

नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हमारा प्रदेश बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार व राजस्थान सरकार ने मिलकर जन कल्याण में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की है, परंतु अशोक गहलोत राजस्थान में असफल विपक्ष के रूप में मिथ्या प्रचार के माध्यम से प्रदेश में नकारात्मकता का वातावरण निर्मित कर रहे हैं।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पिछली गहलोत सरकार के समय में राजस्थान विद्युत अभाव के कारण अंधकारग्रस्त रहा। अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के हितों को बंधक बनाकर रखा जाता था। प्रदेश की जनता को मिलने वाली बिजली से संबंधित ऐसे समझौते किये गए, जिससे हमें गर्मी में पीक ऑवर में बिजली वापस लौटानी पड़ी। परंतु वर्तमान में जब हमारी सरकार अबाधित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है, तब वे निम्न स्तर की राजनीति का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो अशोभनीय, निंदनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण है।

'नीट-यू.जी. 2024 का पेपर लीक हुआ था यह बात एन.टी.ए. ने स्वीकार की है'

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम यह जानना चाहते हैं कि क्या नीट-यू.जी. पेपर लीक उन्हीं केन्द्रों तक सीमित था

- सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी पेपर लीक के आधार पर नीट परीक्षा दोबारा करवाने की मांग कर रही याचिकाओं की सुनवाई के दौरान की।

नयी दिल्ली, 18 जुलाई। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि स्नातक स्तर के मेडिकल और अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिले से संबंधित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट यूजी) 2024, शुरू होने से पहले इसका पेपर लीक हो गया था, यह बात केन्द्र सरकार ने स्वीकार कर ली है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ,न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के दौरान इस बात पर भी जोर दिया कि दोबारा परीक्षा इस ठोस आधार पर होनी चाहिए कि पूरी परीक्षा प्रभावित हुई है। शीर्ष अदालत के समक्ष केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पटना और हजारीबाग में प्रश्न पत्र सार्वजनिक होने की घटना को स्वीकार करते हुए कहा कि इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) की ओर से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने इस मामले में बड़े पैमाने पर किसी प्रकार की अनियमितता से साफ तौर पर इन्कार किया।

पीठ ने केंद्र सरकार, परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) और कई याचिकाओं के अधिवक्ताओं की दलीलें विस्तार पूर्वक सुनीं। इसके बाद पीठ नक सभी केंद्रों के अलग-अलग परीक्षा परिणाम शनिवार दिन के 12 तक घोषित करने का आदेश दिया।

पीठ ने कहा, "पटना और हजारीबाग में प्रश्न पत्र सार्वजनिक होने की बात स्वीकार की गई है...प्रश्नपत्र प्रसारित किए गए थे। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह केवल उन्हीं केंद्रों तक सीमित था या बड़े पैमाने पर।"

शीर्ष अदालत ने कहा, "विद्यार्थी परेशान हैं, क्योंकि उन्हें परिणाम नहीं पता। हमे केंद्रवार अंकों का पैटर्न देखना चाहिए। हम चाहते हैं कि परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की पहचान उजागर किए बिना सभी परिणाम घोषित किए जाएं।"पीठ ने जांच के मामले में कहा, "वर्तमान में जांच चल रही है। सीबीआई ने जो (अदालत को) बताया, उसे सार्वजनिक होने से जांच प्रभावित होगी।" पीठ ने कहा कि वह सोमवार को सीबीआई और पटना पुलिस की जांच के मामले में गौर करेगी।

पीठ ने याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील से यह भी पूछा, "आपको यह दिखाना होगा कि प्रश्न पत्र सार्वजनिक होने की घटना इतनी व्यवस्थित थी कि इसने पूरी परीक्षा व्यवस्था को प्रभावित किया ताकि पूरी परीक्षा रद्द की जा सके।"

पीठ ने वकील से पूछा, "अगर हम आपकी विस्तृत दलीलों को स्वीकार करते हैं तो हम आपकी सहायता चाहते हैं कि जांच किन बिंदुओं पर होनी चाहिए।" इस पर संबंधित अधिवक्ता ने कहा, "एनटीए ने पूरे नतीजे घोषित नहीं किए, जबकि यूपीएससी सभी परीक्षार्थियों के नतीजे घोषित करता है। कम से कम एनटीए को उन एक लाख लोगों के नतीजे घोषित करने चाहिए, जिन्हें प्रवेश मिलेगा।"

आर.ए.एस...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भर्ती से वंचित रह जाएंगे और अपील दायर करने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि परीक्षा परिणाम घोषित होने और मॉडल उत्तर कुंजी जारी करने के बाद अभ्यर्थियों को अपनी आपत्तियां पेश करने के लिए तीन दिन का समय दिया गया था। वहीं हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले 569 याचिकाकर्ताओं में से 476 ने तो प्रश्नों पर कोई आपत्ति ही दर्ज नहीं कराई। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि विशेषज्ञों ने आपत्तियों का निपटारा कर कुछ प्रश्नों को डिलीट किया और उत्तर कुंजी के शेष प्रश्नों के जवाबों को सही माना। ऐसे में अपीलार्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद खंडपीठ ने याचिका को सुनवाई के लिए लंबित रखते हुए अपीलार्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है।

'सौ विधायक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तथा आदित्यनाथ के बीच संबंध कुछ खास अच्छे नहीं हैं। आपसी बातचीत में राज्य के कई भाजपा नेता, जिनमें लोकसभा चुनाव हारने वाले नेता भी शामिल हैं, मुख्यमंत्री के काम करने के तरीके की आलोचना करते रहे हैं और इसे आम चुनावों में पार्टी की हार का कारण बता रहे हैं।

भील प्रदेश की मांग को लेकर मानगढ़ धाम पर उमड़े चार राज्यों के लोग

बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम पर भील आदिवासियों का महासम्मेलन हुआ, जिसमें चार राज्यों, राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के भील आदिवासियों ने भाग लिया।

- सांस्कृतिक महासम्मेलन में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के अलावा अन्य आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में मौजूद थे।
- भीलों ने आबादी के अनुपात में आरक्षण देने की मांग की।
- सांसद राजकुमार रोत ने कहा, भील प्रदेश की मांग नई नहीं है, हमारी पार्टी पुरजोर तरीके से यह मांग उठा रही है।

बांसवाड़ा, 18 जुलाई (निसं)। भील प्रदेश की मांग को लेकर चार राज्यों का जनसैलाब शहीदी मानगढ़ धाम पर उमड़ता नज़र आया। इन लोगों ने जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। सांस्कृतिक महासम्मेलन में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के अलावा अन्य आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। महासम्मेलन में सर्वसम्मति से भील प्रदेश की मांग का राजनैतिक प्रस्ताव पारित करते हुए केन्द्र सरकार को भेजे जाने का निर्णय लिया गया। प्रस्ताव में गुजरात के अरवल्ली, महीसागर, दाहोद, पंचमहल, सूरत, बडोदरा, तापी, नवसारी, छोटा उदेपुर, नर्मदा, साबरकांठा, बनासकांठा और भरुच, राजस्थान के बांसवाडा, डूंगरपुर, बाडमेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, झालावाड़, राजसमंद, चित्तौडगढ़ , कोटा, बारां, पाली, मध्य प्रदेश के इंदौर, गुना, शिवपुरी, मंदसौर, नीमच, रतलाम, धार, देवास, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बडवानी, अलीराजपुर तथा महाराष्ट्र के नासिक, ठाणे, जलगांव, धुले, पालघर, नंदुरबार, अलीराजपुर को सम्मिलित करते हुए भील प्रदेश बनाने की मांग की गयी।

वक्ताओं ने समाज में विद्वेष फैलाने वाली कई घटनाओं का उल्लेख करते हुए राजनैतिक दलों को आड़े हाथों लिया। पगड़ी उछालने, अमानवीय हरकतें करने जैसी घटनाओं का उल्लेख करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सर्वसमाज हमारे साथ है। महिला वक्ताओं ने भी सिंदूर, मंगल सूत्र जैसी बातों का उल्लेख करते हुए करतल ध्वनियां बटोरीं। सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि भील प्रदेश की मांग नई नहीं है बीएपी पुरजोर तरीके से यह मांग उठा रही है और इस संबंध में एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री से भी मिलेगा।

इन लोगों ने ट्राईबल एरिया में पांचवी अनुसूची लागू करने, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने, बेणेश्वर की 80 प्रतिशत भूमि आदिवासियों के नाम करने, जगपुरा भूकिया घाटोल में सोने की खदानों की नीलामी निरस्त करने, जनगणना में आदिवासी धर्म का कॉलम अलग से जोड़ने जैसी मांग की।

आदिवासी परिवार संस्था की संस्थापक सदस्य मेनका डामोर ने कहा कि आदिवासी महिलाएं पंडितों के बताये अनुसार न चलें। आदिवासी परिवार में सिंदूर नहीं लगाते, मंगलसूत्र नहीं पहनते। उन्होंने बालिका शिक्षा पर भी बल दिया। उन्होंने व्रत, उपवास बंद करने और अपने को हिन्दू नहीं मानने की भी बात की। आदिवासी परिवार के संस्थापक भंवरलाल परमार ने दावा किया कि भील प्रदेश की मांग तो समय पर पूरी होगी इसकी एक प्रक्रिया है।

धरियावाद विधायक थावरचंद मीणा ने कहा कि विधानसभा में भी अलग भील प्रदेश बनाने की मांग उठी है। उन्होंने कहा कि चार राज्यों में बोली, संस्कृति, रीति-रिवाज एक हैं, ऐसे में सब मिलकर भील प्रदेश क्यों नहीं बना सकते। संचालन दिनेश खानन, रंगलाल मईडा, राजेश दामा व दिनेश रोत ने किया और हीरालाल दामा व रामलाल निनामा ने आभार व्यक्त किया।

यू.पी. भाजपा ने प्रदेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अंसतोष का कारण बने।

लोकसभा चुनाव में सपा ने 37 सीटें जीती, जबकि 2019 चुनाव में सपा को 5 सीटें ही मिली थीं। भाजपा की सीटें 62 से घटकर 32 हो गईं। इन नतीजों ने नेतृत्व को स्तब्ध कर दिया जबकि नेतृत्व को उम्मीद थी कि वर्ष के आरम्भ में भव्य राम मंदिर के निर्माण का इसे फायदा होगा।

पार्टी के अपने डेटा के अनुसार, भाजपा का सबसे खराब प्रदर्शन पश्चिमी व वाराणसी क्षेत्र में रहा, जहां पार्टी 28 में से मात्र 8 सीटें जीत पाई। बृज क्षेत्र में पार्टी ने 13 में से 5 सीटें जीतीं।

गोरखपुर क्षेत्र, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, में भाजपा 13 में से 6 सीटें ही जीत पाई। वहीं अवध क्षेत्र जिसमें लखनऊ, अयोध्या, फैजाबाद शामिल है, में पार्टी ने 16 में से 7 और रानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र में पार्टी 10 में से 4 सीटें ही जीत पाई।

केन्द्रीय नेताओं ने प्रदेश नेताओं से मतभेद भुलाकर 10 विधानसभा सीटों के उपचुनावों पर ध्यान केन्द्रित करने को कहा है। एक सूत्र ने कहा कि तब तक नेतृत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। केन्द्रीय नेतृत्व ने हमें विवाद सुलझाने और इस समय कोई शिकायत नहीं करने को कहा है। वरिष्ठ नेता राज्य भर का दौरा करेंगे और जनता व कार्यकर्ताओं से जुड़ने का प्रयास करेंगे।

हाल ही में केन्द्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि सरकारी नौकरी में ओ.बी.सी. कोटा भरा जाए। पटेल की पार्टी अपना दल का कुर्मी जाति में दबदबा है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थकों का कहना है कि प्रशासन पर मुख्यमंत्री की पूरी पकड़ है, राज्य में कानून व्यवस्था चुस्त और अनुशासन है, जिससे भाजपा को राज्यभर में पकड़ बनाने में मदद दी थी।

योगी खेमे के एक विधायक ने कहा, मुख्य मुद्दा था आलोकप्रिय प्रत्याशियों को पुनः टिकट देना। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। बाबा की टिकट वितरण में कोई भूमिका नहीं थी। बतौर मुख्यमंत्री सत्ता में लौटकर उन्होंने अपनी लोकप्रियता, ईमानदारी, निष्ठा साबित की है। केन्द्रीय नेतृत्व भी यह मानता है।"

घुसपैठ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जिनकी पहचान नहीं की जा सकी है। अभियान अभी जारी है तथा इलाके में कुछ और आतकंवादियों के छिपे होने की आशंका है। सेना की श्रीनगर स्थित चिनार कोर ने कहा कि घुसपैठ की कोशिश को सफलतापूर्वक रोक दिया गया है। चिनार कोर ने एक्स पर पोस्ट किया, आज कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में एलओसी पर दो आतंकवादियों को मार गिराने के साथ ही घुसपैठ की कोशिश को सफलतापूर्वक रोक दिया गया है।

गैंगस्टर रोहित गोदारा का साथी अमरजीत विश्नोई इटली से गिरफ्तार

इटली पुलिस ने उसे 8 जुलाई को डिटेन कर लिया था, अब जल्द ही उसे भारत लाया जाएगा

- प्रारम्भिक जांच में सामने आया कि आरोपी इटली की नागरिकता के बिना अपने दोस्त के साथ रह रहा था।
- गिरफ्तार आरोपी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सहित कई राज्यों में "वॉन्टेड" है।

जयपुर, 18 जुलाई। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) की सूचना पर इटली पुलिस ने गैंगस्टर रोहित गोदारा के साथी और राजू ठेहट हत्याकांड के आरोपी, पचास हजार के इनामी गैंगस्टर अमरजीत विश्नोई को सिसली शहर के तरपानी से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सहित कई राज्यों में "वॉन्टेड" हैं। इसकी तलाश में कई बार राजस्थान पुलिस ने भी छापेमारी की थी। आरोपी बीकानेर में हुई एक घटना के बाद से फरार था। फरारी के दौरान उसने राजू ठेहट हत्याकांड में बदमाशों के साथ हथियारों की भी व्यवस्था की थी। अमरजीत बिश्नोई पर हरियाणा में भी एक मर्डर का आरोप है। वह कुरूक्षेत्र, हरियाणा के वीभत्स, सचिन गोधा हत्या काण्ड में संदिग्ध वांछित है। अब जल्द ही उसे भारत लाया जाएगा।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध और एजीटीएफ दिनेश एमएन ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में बताया कि उनकी टीम काफी समय से अमरजीत सिंह को ट्रैक कर रही थी और जब उसकी लोकेशन इटली आई तो यह जानकारी विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय को दी गई और इंटर पोल से रैड कॉर्नर नोटिस जारी कराया गया। इसके बाद उसकी लोकेशन एम्बेसी के जरिए इटली पुलिस को दी गई। इटली पुलिस ने उसे 8 जुलाई को डिटेन कर लिया, अब जल्द ही उसे भारत लाया जाएगा।

दिनेश एमएन ने बताया कि रोहित गोदारा गैंग का यह विदेश में बैठा सबसे सक्रिय गैंगस्टर है। यह इस गैंग के सदस्यों द्वारा फिरौती के लिए धमकी देने में वीपीएन व बॉक्स कॉल के जरिये विदेश में बैठ कर बातचीत करवाता था।

एजीटीएफ की टीम राजू ठेहट के मामले में फरार चल रहे बदमाशों की तलाश में जुटी हुई थी। इस गैंग में सक्रिय अपराधियों और शरण देने वालों तथा सोशल मीडिया के फॉलोअर्स के मोबाइल का विश्लेषण किया गया। मोबाइल विश्लेषण में रोहित गोदारा गैंग के कुख्यात अमरजीत विश्नोई की लोकेशन इटली में होना सामने आया। इंटर पोल को इस की लोकेशन की जानकरी दी गई।

इसके बाद इटली पुलिस ने इटली के सिसली शहर के तरपानी कस्बे में दबिश देकर अमरजीत सिंह बिश्नोई को पकड़ लिया। इटली पुलिस ने राजू ठेहट हत्याकांड के वांटेड अमरजीत सिंह को सीबीआई के जरिये सौंपा हैं। सीबीआई टीम के जरिए जल्द ही राजस्थान पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ करेगी।

पुलिस जानकारी में सामने आया है कि बीकानेर का रहने वाले अमरजीत सिंह के खिलाफ 8 बड़े मामले हरियाणा, राजस्थान, यूपी व दिल्ली में दर्ज हैं। उस पर मर्डर व डकैती से लेकर लूट और हत्या के प्रयास के मुकदमे हैं। राजू ठेहट हत्याकांड से करीब चार माह पहले ही अमरजीत ने उसकी हत्या की प्लानिंग बना ली थी।

उसे पता था कि अगर हत्याकांड प्लानिंग के अनुसार हो गया तो पुलिस उसका पीछा करेगी।

द्रमुक ने वंशवाद के नारे

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

होना एक अग्रिम निष्कर्ष के रूप में ले लिया जायेगा। हाँ, द्रमुक ने यह पहले से ही मान लिया है कि विपक्ष, खास तौर से भाजपा की ओर से इस वंशवादी राजनीति की कड़ी आलोचना की जायेगी, लेकिन तमिलनाडु में, द्रमुक करुणानिधि परिवार का पर्याय हो गई है तथा जनता ने इस परिवार के शासन को कमोबेश स्वीकार भी कर लिया है। उदयनिधि स्टालिन ने चुनाव भी जीता था तथा वे चेन्नई के एक विधानसभा क्षेत्र से विधायक बन गये थे तथा वे उनके पिता स्टालिन के द्वारा ही पार्टी की कमान सँभालने के लिये तैयार किए जा रहे हैं। ज्ञातव्य है कि स्वयं एम.के. स्टालिन ने भी अपने पिता करुणानिधि से लम्बे समय तक राजनैतिक प्रशिक्षण प्राप्त किया था।

उदयनिधि, जो इस समय खेल और युवा मामलों के मन्त्री हैं, को कार्यक्रम-क्रियान्वयन (प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन) का प्रभार और दे दिया जायेगा। इस मन्त्रालय के मन्त्री हो जाने से उन्हें सरकार के सभी विभागों पर नजर रखने का अवसर मिलेगा तथा वे पूरे तमिलनाडु के प्रत्येक विभाग एवं गतिविधि पर नजर रख सकेंगे।

'कांवड़ियों के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में कुछ झगड़े हो चुके हैं। मुजफ्फरनगर के एस.एस.पी अभिषेक सिंह ने इस मामले में कहा कि ये निर्देशात्मक आदेश हर व्यक्ति की सुरक्षा के मद्देनजर जारी किए गए हैं। हालांकि, राजनीतिज्ञ उनकी इस बात से सहमत नहीं है। ए.आई.एम.आई.एम. के अध्यक्ष व हैदराबाद से पार्टी के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस कदम को दक्षिण अफ्रीका में किए गए नस्लीय भेदभाव के साथ तथा हिटलर के जर्मनी में यहूदी व्यापारियों के बहिष्कार की घटना से जोड़ कर देखा जाना चाहिए।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने इस आदेशात्मक कदम को "सामाजिक अपराध" की संज्ञा दी है। अखिलेश यादव ने कोर्ट से आग्रह किया है कि वह इस मामले में स्वतः संज्ञान ले तथा इस आदेश के पीछे सरकार के इरादे की जांच कराए और उचित दंडात्मक कार्यवाही करे।"

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आलोचना करते हुए कहा कि ये तथाकथित निर्देश साम्प्रदायिक एकता की स्थिति, जो समाज के वर्गों व समुदायों में विद्यमान है, को भंग करने के लिए जारी किए गए हैं। दारुल उलूम के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निज़ामी ने कहा "इस प्रकार का सांप्रदायिक पक्षपात गलत है और इस मुद्दे पर ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए।" उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम लोग कांवड़ तीर्थ यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करते हैं और जब ताज़िए निकाले जाते हैं तो हिन्दू भाई भी सहयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि "आज जरुरत इस बात की है कि भाईचारा बनाए रखा जाना चाहिए।"

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा। आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्सः0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्सः 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, 2418945, फैक्सः 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोनः 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोनः 226422, 226423, फैक्सः 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोनः 256906, 256907, फैक्सः01562-256908